Serving Education for Last 40 Years

NEERAJ®

M.P.A.-13

सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन

(Public Systems Management)

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: *Ved Prakash Sharma,* M.A. (Pol. Science)

NEERAJ
PUBLICATIONS
(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com
Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 300/-

Content

सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन

(Public System Management)

Question Paper—June-2024 (Solved) 1-2

Question Paper—December-2023 (Solved) 1

Question Paper—June-2023 (Solved) 1

Question Paper—December-2022 (Solved) 1

Question Paper—Exam Held in March-2022 (Solved) 1-2

Question Paper—Exam Held in August-2021 (Solved) 1-2

Question Paper—Exam Held in February-2021 (Solved) 1-2

Question Paper—June, 2019 (Solved) 1

Question Paper—December, 2018 (Solved) 1-3

Question Paper—June, 2018 (Solved) 1

Question Paper—December, 2017 (Solved) 1

Question Paper—June, 2017 (Solved) 1

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page
1.	सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन : अवधारणा, स्वरूप, कार्यक्षेत्र और विशेषताएँ (Public System Management : Concept, Nature, Scope and Characteristics)	1
2.	सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन की विशिष्टता (Distinctiveness of Public System Management)	8
3.	सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन : संवैधानिक संदर्भ (Public System Management: Constitutional Context)	15
4.	सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन : राजनीतिक संदर्भ (Public System Management: Political Context)	24
5.	सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन : सामाजिक-आर्थिक संदर्भ (Public System Management : Socio-Economic Context)	31
6.	नई प्रौद्योगिकियाँ और सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन (New Technologies and Public System Management)	37

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page

7. शासन व्यवस्था की अवधारणा : परिचय 46
(Concept of Governance : An Introduction)

8. शासन व्यवस्था : नौकरशाही और राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका 52
(Governance: Role of Bureaucracy and Political Executive)

9. शासन व्यवस्था : विधानपालिका और न्यायपालिका की भूमिका 57
(Governance: Role of Legislature and Judiciary)

10. शासन व्यवस्था की प्रक्रिया में अंत:सरकारी संबंध 64
(Inter-governmental Relations in the Process of Governance)

11. वित्तीय प्रबंधन 70
(Financial Management)

12. सामग्री/संभारतंत्र प्रबंधन 77
(Materials/Logistics Management)

13. सामरिक प्रबंधन 84
(Strategic Management)

14. मुख्य प्रबंधन साधन 89
(Key Management Tools)

15. प्रबंधन सूचना प्रणाली 96
(Management Information System)

16. कार्य मापन 102
(Work Measurement)

17. चयनात्मक बाजार तकनीकें 107
(Some Select Market Techniques)

18. भावी डिजाइनिंग तकनीकें 112
(Future Designing Techniques)

19. उत्तरदायित्व 117
(Accountability)

20. सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन में अनुक्रियाशीलता 123
(Responsiveness in Public System Management)

21. पारदर्शिता और सूचना का अधिकार 128
(Transparency and Right to Information)

22. शासन-व्यवस्था में नेटवर्किंग और अंत:संस्थागत समन्वयन 133
(Networking and Inter-institutional Co-ordination in Governance)

23. सुधार और परिवर्तन प्रबंधन 137
(Reforms and Change Management)

24. सशक्तीकरण 144
(Empowerment)

25. सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन में निरंतरता और परिवर्तन 152
(Continuity and Change in Public System Management)

■■

Sample Preview of the Solved Sample Question Papers

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS
www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2024

(Solved)

सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन

(Public System Management)

M.P.A.-13

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

नोट : *किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग में से कम-से-कम दो प्रश्न कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।*

भाग-I

प्रश्न 1. लोक सेवा के बदलते स्वरूप पर एक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-2, पृष्ठ-9, 'लोक सेवा का बदला स्वरूप'

प्रश्न 2. ''शासन की अवधारणा का प्रयोग कई संदर्भों में किया जाता है।'' टिप्पणी कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-7, पृष्ठ-46, 'शासन की अवधारणा', पृष्ठ-47, 'शासन : प्रासंगिक प्रयोग'

प्रश्न 3. सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन के राजनीतिक संदर्भ की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-4, पृष्ठ-24, 'राजनीतिक संदर्भ'

प्रश्न 4. नौकरशाही और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच संबंधों के बदलते स्वरूप का परीक्षण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-8, पृष्ठ-53, 'नौकरशाही और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच संबंधों के प्रारूप'

प्रश्न 5. निम्नलिखित में से प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए–

(क) नेटवर्क समाज

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-6, पृष्ठ-37, 'नेटवर्क समाज'

(ख) जनहित याचिका

उत्तर–'जनहित याचिका' शब्द अमेरिकी न्यायशास्त्र से लिया गया है, जहां इसे पहले से अप्रतिनिधित्व प्राप्त समूहों जैसे गरीबों, नस्लीय अल्पसंख्यकों, असंगठित उपभोक्ताओं, पर्यावरण संबंधी मुद्दों के प्रति संवेदनशील नागरिकों आदि को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था।

जनहित याचिका (पीआईएल) का अर्थ है–प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माण संबंधी खतरे आदि जैसे 'सार्वजनिक हित' की सुरक्षा के लिए कानून की अदालत में दायर मुकदमा। कोई भी मामला जहां बड़े पैमाने पर जनता का हित प्रभावित होता है, कानून की अदालत में जनहित याचिका दायर करके उसका निवारण किया जा सकता है।

जनहित याचिका को किसी भी कानून या अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। न्यायाधीशों द्वारा इसकी व्याख्या आम जनता की मंशा को ध्यान में रखकर की गई है।

जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायालयों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है। हालांकि याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को न्यायालय की संतुष्टि के लिए यह साबित करना होगा कि याचिका जनहित के लिए दायर की जा रही है, न कि किसी व्यस्त निकाय द्वारा एक तुच्छ मुकदमे के रूप में।

न्यायालय स्वयं मामले का संज्ञान ले सकता है और स्वप्रेरणा से आगे बढ़ सकता है या किसी लोक हितैषी व्यक्ति की याचिका पर भी मामला शुरू किया जा सकता है।

जनहित याचिका के अंतर्गत विचारणीय कुछ मामले इस प्रकार हैं–बंधुआ मजदूरी के मामले, उपेक्षित बच्चे, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना तथा अनियमित श्रमिकों का शोषण, महिलाओं पर अत्याचार, पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिकी संतुलन में गड़बड़ी, खाद्य पदार्थों में मिलावट, विरासत और संस्कृति का रखरखाव।

भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के बीज सर्वप्रथम न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा 1976 में मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई मामले में बोये गये थे।

जनहित याचिका का पहला मामला हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979) था, जो जेलों और विचाराधीन कैदियों की अमानवीय स्थितियों पर केंद्रित था, जिसके कारण 40,000 से अधिक विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया था।

त्वरित न्याय का अधिकार एक बुनियादी मौलिक अधिकार के रूप में उभरा, जिसे इन कैदियों को देने से मना कर दिया गया था। बाद के मामलों में भी यही पैटर्न अपनाया गया।

एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती द्वारा जनहित याचिका आंदोलन के एक नए युग की शुरुआत की गई।

इस मामले में यह माना गया कि 'सद्भावनापूर्वक कार्य करने वाला कोई भी सार्वजनिक या सामाजिक कार्य समूह का सदस्य'

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226 के तहत) या सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32 के तहत) के रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान कर सकता है, ताकि उन व्यक्तियों के कानूनी या संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध निवारण की मांग की जा सके, जो सामाजिक या आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते।

इस निर्णय के द्वारा जनहित याचिका 'सार्वजनिक कर्त्तव्यों' के प्रवर्तन के लिए एक शक्तिशाली हथियार बन गई, जहां कार्यकारी कार्रवाई या गलत काम के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षति हुई हो। और परिणामस्वरूप भारत का कोई भी नागरिक या कोई भी उपभोक्ता समूह या सामाजिक कार्य समूह अब देश के सर्वोच्च न्यायालय में उन सभी मामलों में कानूनी उपाय की मांग कर सकता है जहाँ आम जनता या जनता के एक वर्ग के हित दांव पर लगे हों।

न्यायमूर्ति भगवती ने यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ किया कि जनहित याचिकाओं की अवधारणा को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया जाए। उन्होंने प्रक्रियागत तकनीकी पहलुओं के पालन पर जोर नहीं दिया और यहां तक कि जनहितैषी व्यक्तियों के साधारण पत्रों को भी रिट याचिकाओं के रूप में माना।

भाग-II

प्रश्न 6. ''लेखा परीक्षण तथा संसदीय नियंत्रण, भारत में बजट पर नियंत्रण के दो तरीके हैं।'' व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-11, पृष्ठ-72, 'बजट पर नियंत्रण'

प्रश्न 7. माल-सूची नियंत्रण की अवधारणा और तकनीकों की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-12, पृष्ठ-79, 'सामान सूची नियंत्रण : अवधारणा और तकनीक'

प्रश्न 8. व्यवस्था विश्लेषण की अवधारणा और दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-14, पृष्ठ-92, 'व्यवस्था विश्लेषण : अवधारणा और दृष्टिकोण', पृष्ठ-93, 'व्यवस्था विश्लेषण चरण'

प्रश्न 9. विभिन्न सामूहिक निर्णय तकनीकों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-18, पृष्ठ-113, 'सामूहिक निर्णय तकनीकें'

प्रश्न 10. निम्नलिखित में से प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए–

(क) उत्तरदायित्व के प्रकार

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-19, पृष्ठ-118, 'उत्तरदायित्व के प्रकार'

(ख) कार्य मापन के मूलभूत तत्व

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-16, पृष्ठ-103, 'कार्य मापन के मूलभूत तत्व'

■■

NEERAJ PUBLICATIONS
www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

Sample Preview of The Chapter

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS
www.neerajbooks.com

सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन

(Public System Management)

सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन : अवधारणा, स्वरूप, कार्यक्षेत्र और विशेषताएँ

(Public System Management : Concept, Nature, Scope and Characteristics)

1

NEERAJ PUBLICATIONS
www.neerajbooks.com

परिचय

सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन लोक प्रशासन के विकास के मार्ग में जोड़ा गया एक प्रभावपूर्ण विचार है। वैश्वीकरण के दौर में आज सरकार और राज्य की भूमिका पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। विश्व के सामाजिक और आर्थिक स्तर पर समसामयिक विकास में निरन्तर परिवर्तन के कारण लोक प्रशासन के विषय और व्यवहार दोनों ही क्षेत्रों में बदलाव हो रहा है। लोक प्रशासन ने राज्य, समाज और बाजार के मध्य संबंध को उच्च स्तर पर देखे जाने की आवश्यकता उत्पन्न कर दी है अंततः सन 1980 से शासन का बाजारोन्मुखी स्वरूप दिखाई देने लगा। अब प्रशासक एक व्यवसायी के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, जिनका कार्य सरकारी खर्च को कम करना और कार्य को महत्त्वपूर्ण ढंग से करना है। उनसे आशा की जा रही है कि वे बाजार के संकटों से डटकर मुकाबला करें और अच्छे परिणाम लाने में सक्षम हों। वस्तुतः अब सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन में एक नया अध्याय जोड़ दिया गया है, जिसमें लोक प्रशासन की संरचना एवं कार्यपद्धति सम्मिलित है। इस अध्याय के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन की अवधारणा, सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन की विशेषताएं, सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन का स्वरूप एवं सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन के कार्यक्षेत्र की चर्चा की गई है।

अध्याय का विहंगावलोकन

सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन : अवधारणा

सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन का कार्य किसी संस्था के अन्तर्गत आने वाले अन्य लघु संगठनों के मध्य तालमेल और उनके व्यवहार में समरूपता लाना है। जैसे बाजार कई छोटी-छोटी इकाइयों का एक बड़ा समूह होता है। सभी संस्थाओं का एक निर्धारित उद्देश्य होता है, जिसके लिए वे एक व्यवस्था का निर्माण करती हैं। सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन विस्तृत रूप में व्यक्तियों की आवश्यकताओं, नियम-विनियमों और सार्वजनिक उपक्रमों के अनुसार कार्य करता है। सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन का एक विशेष प्रकार के दायरे में कार्य करने का अनोखा तरीका होता है, जो विभिन्न क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में अलग-अलग भी हो सकता है। इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन निजी क्षेत्र के सिद्धांतों और कार्य-शैली के अनुसार ही कार्य करे। सार्वजनिक प्रबंधन सुधार

www.neerajbooks.com

व्यावसायिक प्रबंधन से प्रभावित है, जहां संस्थानों के प्रबंधकों को निर्णय लेने की स्वायत्तता प्राप्त होती है। लोक सेवा और सरकार की कार्य प्रणाली की व्यवस्था बनाने और इसे सुचारु रूप से चलाने में सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह एक प्रकार से राज्य कर्मचारियों की गलतियों को सुधारने और सरकार को व्यवस्थित रखने का प्रयास करता है।

लोक प्रशासन सदा से ही व्यक्तियों की आवश्यकता, रुचि, समानता, संसाधनों की जिम्मेदारी निभाने में एक प्रतिनिधि की भूमिका अदा करता है। लेकिन नौकरशाही ने नियम-कानून, पदसोपानों पर आवश्यकता से अधिक विश्वास समय के साथ इसकी गति और प्रभाव पर अनेक प्रश्न उत्पन्न किए हैं। लोगों पर करों का बढ़ता बोझ और खर्च, राज्य नौकरशाही की कार्यशैली और तंत्र, अविश्वास और वैश्वीकरण के प्रभाव ने सार्वजनिक प्रणाली में प्रबंधन, उद्देश्य और कार्यपद्धति को बढ़ावा दिया और परिणामस्वरूप लोक प्रशासन में कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिससे सार्वजनिक प्रणाली के स्वरूप और प्रकृति में महत्त्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते हैं। इस समस्त प्रक्रिया को चार भागों में बाँटा जा सकता है–

1. निजीकरण और अनियमितीकरण
2. विकेन्द्रीकरण
3. नौकरशाही विहीनीकरण और
4. बाजार पर आधारित गतिविधियों को व्यवस्थित करना

उपर्युक्त सभी पद्धतियाँ सार्वजनिक प्रणाली को प्रतियोगात्मक बनाने का इशारा करती हैं, जिसका आधार एक सुदृढ़ प्रबंधन हो। सरकारी प्रणाली में अब विश्व स्तर पर एक नई प्रकार की तकनीक अपनायी जा रही है। सार्वजनिक संस्थाएँ अब निजी प्रबंधन के अनेक माध्यमों से चलाई जा रही हैं। वर्तमान में सार्वजनिक प्रणाली के ये प्रारूप कितने सक्षम और महत्त्वपूर्ण हैं, इसी से लोक प्रशासन के अन्य सुदृढ़ प्रारूपों की खोज प्रारम्भ की गई। सार्वजनिक प्रणाली में आए इन बदलावों ने सार्वजनिक संगठनों में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निभाई है और सार्वजनिक प्रणाली की कार्यशैली की बाजारोन्मुखी छवि प्रस्तुत की। प्रशासनिक व्यवस्था के इन नवीन प्रारूपों को नव-लोक प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। इन परिवर्तनों के सैद्धांतिक आधारों की जानकारी में इससे जुड़े बहुत सारे विषयों, जैसे–नव-दक्षिणपंथी विचारधारा, लोक चयन दृष्टिकोण, संपत्ति अधिकार से जुड़ा अध्ययन, प्रधान-एजेंट सिद्धांत, संस्था और प्रबंधन के उद्देश्य सम्मिलित किए जा सकते हैं।

1. नव-दक्षिणपंथी विचारधारा (New Right Philosophy)–सर्वप्रथम सन 1970 में शिकागो विश्वविद्यालय ने वित्तीय कार्यों से संबंधित एक समूह को नव-दक्षिणपंथी विचारधारा का प्रस्ताव दिया। नव-दक्षिणपंथी विचारधारा का प्रमुख सिद्धांत यह था कि सरकार अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि इससे बाजार खराब होता है और परिणाम विपरीत होते हैं। विस्तृत रूप से देखा जाए तो यह बाजार में राज्य के एकाधिकार को बढ़ावा देता है, उद्यमशीलता को दबाता है, आवश्यक वस्तुओं को कम करता है और अनावश्यक वस्तुओं को बढ़ावा देता है। नव-दक्षिणपंथी विचारधारा की सुधार प्रक्रिया में कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर जोर दिया गया है, जो इस प्रकार हैं–1. मुद्रा स्फीति को कम करना, 2. कम कर और साथ ही लोक सेवा, 3. संस्थात्मक और विधायी क्षेत्र के सुधार में बाजार की बढ़ती भूमिका। नव-दक्षिणपंथी विचार हमेशा व्यक्तिगत अधिकार और चयन को प्रमुखता देता है।

2. लोक चयन दृष्टिकोण (Public Choice Approach)–लोक चयन दृष्टिकोण का मानना है कि लोक सेवा में लचीलेपन के लिए नौकरशाही उत्तरदायी है। इसमें ग्राहक हो या प्रबंधक, दोनों ही शुद्ध लाभ के लिए किसी वस्तु की शुद्धता की अधिकता को जांचते हैं। लोक चयन दृष्टिकोण के लोक अध्ययन के तीन दृष्टिकोण हैं–विल्सोनियन की राजनीति : प्रशासन का द्विभाजन, वेबेरियन नौकरशाही, हर्बर्ट साइमन का तार्किक निर्णय लेने का मॉडल। विशेष रूप से लोक चयन दृष्टिकोण निम्नलिखित नीति निर्धारकों पर बल देता है–

1. सरकारी संस्थाओं की क्रिया को नियंत्रित करना
2. प्रशासन की भूमिका को कम करना
3. न्यूनतम की ओर, लोगों के एकाधिकार को कम करना
4. राजनीतिज्ञों की दखलंदाजी को सीमित करना।

आमतौर पर लोक चयन सिद्धांत को मानने वाले सरकारी संस्थाओं को शक की नजर से देखते हैं। लोक चयन की महत्त्वपूर्ण पहल है विकेन्द्रीकरण, लोकतांत्रिक प्रशासन और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। ब्यूकॉनैन और ट्यूलॉक के अनुसार विकेन्द्रीकरण सरकारी संस्थाओं में प्रतियोगिता के अवसर को बढ़ाने एवं निजी तौर पर लोक चयन को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

3. संपत्ति पर अधिकार का सिद्धांत (Property Rights Theory)–संपत्ति पर अधिकार का सिद्धांत एक नवीन दृष्टिकोण है, जिसमें कार्यशैली के अनुसार प्रोत्साहन दिया जाता है। संपत्ति पर अधिकार से संबंधित जानकारी से पता चलता है कि संपत्ति पर अधिकार स्थिर नहीं हो सकता। इस व्यवस्था में हो रहे बदलाव का श्रमिकों के श्रम और उनके आचरण पर दूरगामी असर होगा। डनसायर मानते हैं कि निजी संस्थाओं में लाभ पर अधिकार स्पष्ट रूप से दिखता है, वहीं सार्वजनिक क्षेत्रों में यह अनिश्चित ही दिखाई देता है।

4. प्रधान-एजेंट सिद्धांत (Principal-agent Theory)–संपत्ति पर अधिकार में परिवर्तन से किसी भी उद्योग के मालिक एवं

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

प्रबंधन के मध्य के संबंधों में परिवर्तन आता है। इस सिद्धांत के अनुसार मालिक प्रधान होता है और प्रबंध एजेंट है, लेकिन इन दोनों के उद्देश्य भिन्न हैं। प्रधान-एजेंट सिद्धांत राजनीतिक और सामाजिक जीवन के नियमों पर आधारित होता है। नियम प्रधान बनाता है, जिसमें सेवा के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और कार्यक्षमता निर्धारित की जाती है।

5. संगठन और प्रबंधन अध्ययन–नौकरशाही के वेबेरियन मॉडल का आलोचक संगठन और प्रबंधन का अध्ययन है, जो संगठन के अंदरूनी भागों पर निर्भर है। ये अध्ययन व्यक्तिगत क्षेत्रों में कार्यशैली की संस्कृति को बढ़ाते हैं। अधिकांश देशों ने सार्वजनिक व्यवस्था के ढांचे को इस प्रकार तैयार किया है जिससे यह राज्य की भूमिका को सीमित करता है, साथ ही नौकरशाही को बढ़ावा नहीं देता। जैसे–अच्छे परिणाम प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार करना, कीमतों को कम करना, बाजारीकरण और सरकारी क्रियाकलापों को बाजार के अनुसार बनाना, सरकार की कुछ नियंत्रित प्रक्रियाओं को अनुबंधित करना आदि। विस्तृत बाजार का तात्पर्य कम सरकार नहीं है, अपितु वह सरकार, जो विभिन्न प्रकार से कार्य करती हो। कुछ विचारकों ने इसकी प्रमुख तीन अवधारणाएँ मानी हैं–

1. संगठन का पुनर्निर्माण, स्वायत्त और अर्द्धस्वायत्त संस्थाओं का निर्माण, कनिष्ठ प्रबंधकों द्वारा निर्णय लेने की व्यवस्था को केन्द्रीयकृत प्रशासन से विकेन्द्रीयकृत प्रबंधन पर दबाव डालने के लिए लागू करना।
2. काम को विस्तृत करना, सेवाओं के लिए शुल्क वसूलना, निजीकरण और अनुबंध लागू करना, साथ ही सेवा प्रदाताओं पर नियंत्रण करना और सेवाओं को ग्राहकों के प्रति उत्तरदायी बनाना ताकि इन्हें बाजार की जरूरतों के अनुसार बनाया जा सके।
3. प्रदर्शन पर जोर अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र में व्यापार को नियमों के अनुपालन के अलावा नतीजे प्राप्त करने की ओर ले जाने का प्रयास करना।

सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन : स्वरूप

अधिकांश लोगों ने सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन को प्रशासन और प्रबंधन दोनों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संस्था के रूप में देखा है, जो सार्वजनिक नीति निर्धारण और सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करती है। यह प्रबंधन की एक विशेषता है जो उद्देश्यों पर दबाव डालती है, सामयिक अनुबंध को सीमित करती है, प्रबंध की स्वतंत्रता तथा आर्थिक पारितोषिक का समर्थन करती है। सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन का उद्देश्य नतीजे, प्रदर्शन और परिमाण पर आधारित होता है। यह सार्वजनिक संगठनों के कार्यों में निम्नलिखित परिवर्तन लाता है–

1. परिणामों पर ध्यान देना।
2. निजी क्षेत्र की श्रमिक नीतियों को अपनाने पर बेहतर प्रदर्शन को अधिक और खराब प्रदर्शन को कम भुगतान किया जाता है।
3. यह अनिवार्य रूप से अनुशासित वेबेरियन मॉडल के अनुसरण की अपेक्षा संगठन को परिस्थितिनुसार बनाने हेतु लचीला होता है।
4. सामरिक योजना पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन शासन में प्रबंधन के तौर-तरीकों का प्रचार निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार करता है–

1. सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण के अनुपयुक्त क्षेत्रों के लिए बाजार की मांग पर ढांचा तैयार करना।
2. परिणामों से सरोकार रखना।
3. सरकार की भूमिका केवल संचालनकर्ता की होनी चाहिए।
4. उपभोक्ता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना।

सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन की विशेषता 'सार्वजनिकता' है। रैनसन और स्टीवर्ट (1994) सार्वजनिक क्षेत्र की इस विशेष बात को गर्मजोशी के साथ प्रस्तुत करते हैं कि यह प्रशासन के सिद्धांतों को कम कर सकता है। सार्वजनिक संगठन में लक्ष्यों को प्राप्त करने में सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन अधिक सहयोग देता है। सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन अधिक संवेदनशील, कुशल और कम लागत पर सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराने का प्रयास करता है।

सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन : कार्यक्षेत्र

वर्तमान में सरकारें कार्यशैली पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही हैं। इसलिए आवश्यकता है कि शासन का प्रबंधन से नियंत्रण समाप्त हो। सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधक किसी भी प्रकार के संकट का मुकाबला करने वाला होना चाहिए, जो दूसरे प्रकार के संगठनों को भी अपने साथ जोड़ सके और प्रदर्शन के आधार पर प्रतिफल दे सके। इस परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन का लक्ष्य शासन के निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है–

1. प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देने की बजाय नतीजे प्राप्त करने पर ध्यान।
2. परिणामोन्मुख बनाने के लिए शासन का नियंत्रण कम करना।
3. ग्राहकों की सेवा के लिए कर्मचारियों को सशक्त करना जो समूह कार्य को शक्तिशाली बनाए।

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

4. सेवा के सिद्धांत और कुशलता को बनाए रखने के लिए लोक प्रशासन को उपभोक्ताओं की इच्छानुसार बनाना।
5. सरकारी भूमिका को संचालक बनाना न कि स्वयं काम करना, नीतियों के क्रियान्वयन के लिए अलाभकारी संगठनों और शासन के अन्य स्तरों पर निर्भर करना।
6. सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तु व सेवा प्राप्त करवाने में प्रतियोगिता व अनुबंध जैसे बाजार के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना।
7. लोक प्रशासन की संपूर्ण संस्कृति को लचीली, नवीनीकरण, उद्यमशीलता की ओर ले जाना, प्रक्रियान्मुख के प्रतिकूल बनाना, वस्तुओं की आगत पर ध्यान न देकर परिणाम पर ध्यान देना।
8. सार्वजनिक प्रणाली में प्रदर्शन के मापन, संस्था को स्वायत्तता और व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर दबाव डालती हुई नई उद्यमशीलता, ग्राहकोन्मुख संस्कृति की रचना करना।

कैटल (2002) नव-लोक प्रबंधन की प्राथमिकताओं के मुख्य पहलुओं की ओर इशारा करता है, जो इस प्रकार हैं–

1. उत्पादनशीलता–सरकारें कम आमदनी के साथ अधिक सेवाएं कैसे दे सकती हैं?

2. बाजारीकरण–सरकारें नौकरशाही की कमियों को दूर करने के लिए बाजार की मांग पर इनाम देने की शैली का प्रयोग कैसे कर सकती हैं?

3. सेवोन्मुख–सरकारें योजनाओं को लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए लोगों से अच्छे संबंध कैसे बना सकती हैं?

4. विकेन्द्रीकरण–सरकारें लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए, योजनाओं को शासन के निम्न स्तर तक स्थानांतरित करके प्रबंधकों को बेहतर प्रोत्साहन और क्षमता देकर योजनाओं को अधिक जिम्मेदार और प्रभावी कैसे बना सकती हैं?

5. नीति–सरकारें नीति बनाने और उनको लागू करने की क्षमता कैसे बढ़ा सकती हैं?

परिणाम के लिए जवाबदेही–सरकारें अपनी क्षमताओं को कैसे बढ़ा सकती हैं? जिससे वह अपनी समस्त सेवाएं प्रदान कर सकें, जिसका उन्होंने वायदा किया था।

उपर्युक्त सभी सरोकारों को प्रभाव में लाने के लिए सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन दबाव डालता है। इसका लक्ष्य निजी क्षेत्र के सिद्धांतों और व्यवहार के आधार पर लोक सेवा को अधिक प्रभावशाली और कुशल बनाकर ग्राहक की पसंद को जनता की पसंद मानना है।

सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन : विशेषताएँ

सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन की महत्त्वपूर्ण विशेषता नतीजों को प्राप्त करने की प्रबंधकों की जिम्मेदारी है, जिसके अन्तर्गत राजनीतिज्ञ और प्रबंधकों के मध्य संबंध पहले से अधिक मधुर होते हैं। सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन शासन में केन्द्रीय संस्था के नियंत्रण को कम और प्रबंधन स्वायत्तता को बढ़ाने और जनता की भावना का सम्मान करने पर बल देती है। शासन को सुदृढ़ बनाने के तरीकों में निम्नलिखित विशेषताओं के माध्यम से सुधार लाया जा सकता है–

1. यह नौकरशाही ढांचे की बजाय बाजार के ढांचे को अधिक महत्त्व देता है।
2. यह प्रशासनिक समस्याओं को उत्पन्न होने से रोकता है।
3. इसका प्रमुख उद्देश्य सेवा प्रदान करना है, जिसको जनता पसंद करे।
4. यह व्यक्ति और संगठन के प्रदर्शन को शक्ति से परखता है।
5. यह कामकाज की परिस्थितियों को अधिक सरल बनाता है।
6. यह प्रबंधन मॉडल भागीदारी को पसंद करते हुए सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर जोर देता है।
7. यह सार्वजनिक सेवाएं प्रदान कर सामुदायिक समस्याओं का समाधान करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में अधिक सहयोग स्थापित करता है।
8. यह प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़ कर भाग लेता है और सार्वजनिक संगठन के प्रबंधन के लिए अपना रवैया खुला रखता है।

सार्वजनिक प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं–

1. समस्त प्रकार के कार्यों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग।
2. सरकारी कर्मचारियों को नई भूमिका दी जाए, तकनीकी प्रतियोगिता का शिक्षण, नीति-निर्धारण क्षमता के साथ प्रबंधन का कौशल हो।
3. प्रक्रिया और नियम के पालन के अलावा उच्च स्तर की पारदर्शिता और जवाबदेही।
4. क्रियाकलापों, अनुबंधों और बाहरी स्रोतों का विकेन्द्रीकरण किया जाए और शासन सामरिक क्षेत्रों पर नियंत्रण करे।
5. कौशल को परखकर, प्रोत्साहन व्यवस्था बनाकर, विभिन्नता के अनुरूप वेतन देकर सार्वजनिक प्रणाली

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com